

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2018—आश्विन 20, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 30 तथा 31 अगस्त, 2018 (02 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् 01 तथा 02 सितम्बर, 2018 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 4-13/2018/11/6.—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, (संशोधित 1998), क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा-4 की उपधारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी सारिणी के कालम नं.-2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारिणी के कालम नं.-4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कालम नं.-3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्ति करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम/पद	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, की धाराएँ	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर.आर. राजभानू, सहायक पंजीयक	(1) धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39 (2) महिला स्व. सहायता समूह, महिला मंडल, नवयुवक मंडल श्रेणी के सभी संभागों की समितियों का अधिनियम की धारा-34 के अधीन पंजीयन, निरस्तीकरण.	छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की संस्था
2.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग
3.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	दुर्ग संभाग
4.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	रायपुर एवं बस्तर संभाग

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 20-22/2015/11/6.—औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं की पात्रता प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी में होने उद्योग संचालनालय स्तर पर प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 15/औ.नीति/2015/13300-13326, दिनांक 11-07-2016 के तहत ऑनलाईन जारी किया गया है, जिसके बिन्दु क्रमांक-26 में प्राथमिकता श्रेणी का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने पर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अपील की जाने का प्रावधान दिया गया है. किन्तु इसकी प्रक्रिया इत्यादि निर्धारित नहीं की गई है.

उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 15/औ.नीति/2015/13300-13326, दिनांक 11-07-2016 की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने, समयावधि व्यतीत होने पर, ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने इत्यादि की स्थिति में औद्योगिक इकाईयों को अपना पक्ष रखने एक अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार अपीलीय प्रावधान निर्धारित किया जाता है :—

1. संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय के आदेश विरुद्ध अपील 45 दिवस के भीतर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी.

2. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रु. 1000/- एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2000/- का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी. अपील शुल्क का भुगतान चालान/ई-चालान के माध्यम से विभागीय प्राप्ति बजट शीर्ष “0852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां, 0674-अन्य प्राप्तियां” में करना होगा.
3. अपीलीय अधिकारी को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होगा.
4. अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को निर्णय लिये जाने के पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जावेगा.
5. अपील मान्य किये जाने पर एन.आई.सी. के माध्यम से ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी करने आवश्यक कार्यवाही उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की जावेगी.

सह अधिसूचना औद्योगिक नीति 2014-19 के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-85 (1) के तहत राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2018 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है.

2. चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है.
3. चयन समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनोद देशमुख, एडवोकेट को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.
4. श्री विनोद देशमुख, एडवोकेट की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी.
5. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी.
6. श्री विनोद देशमुख, एडवोकेट को देय वेतन, भत्ते के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-85 (1) के तहत राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 06 जुलाई 2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है.

2. चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है.

3. अतः चयन समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी. एस. मिश्र, (भा.प्र.से.) सेवानिवृत्त को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है।
4. श्री डी. एस. मिश्र, (भा.प्र.से.) सेवानिवृत्त की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी।
5. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी।
6. श्री डी. एस. मिश्र, (भा.प्र.से.) सेवानिवृत्त को देय वेतन, भत्ते के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे।

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा श्री डी. एस. मिश्र (भा.प्र.से.) सेवानिवृत्त को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उक्त आदेश के जावक में टंकण त्रुटिवश “दिनांक 17 जुलाई, 2018” हो गया है जिसे “दिनांक 17 सितम्बर, 2018” पढ़ा जावे।

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा श्री विनोद देशमुख, एडवोकेट को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है।

उक्त आदेश के जावक में टंकण त्रुटिवश “दिनांक 17 जुलाई, 2018” हो गया है जिसे “दिनांक 17 सितम्बर, 2018” पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 5-22/2012/18.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा-43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि जिला-कोरबा के स्थानीय सुलहकार (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ (इंटक), बालको नगर कोरबा (छ.ग.) एवं अध्यक्ष, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा (छ.ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है।

अनुसूची

संराधक एवं सहायक श्रमायुक्त कोरबा द्वारा प्रस्तुत असफल प्रतिवेदन क्रमांक/ब.फ./स.श्र.आ.को./2011/1810, दिनांक 28-10-

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 5-22/2012/16.—चूँकि अध्यक्ष, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड कोरबा (छ.ग.) के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ (इंटक), बालको नगर कोरबा (छ.ग.) द्वारा किया जा रहा है तथा अध्यक्ष, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड कोरबा (छ.ग.) के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है।

और चूँकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है और इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतः छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा-51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता है।

अनुसूची

क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा समझौता/ठहराव दिनांक 23-03-2005 (एल.टी.एस.VII) के कण्डिका 5.5 का उल्लंघन निरंतरित रूप से किया जा रहा है ? यदि हां तो श्रमिक पक्ष किन लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं कब से ? तथा प्रबंधन को क्या निर्देश दिया जाना न्याय संगत होगा ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 4-8/2006/32.—श्री सुनील मिश्रा, भा.व.से. (1994) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC), छत्तीसगढ़, रायपुर जिनकी सेवाएं समान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं, को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 (2) (एफ) तथा सहपठित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सदस्य-सचिव की अर्हताओं, सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5 के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पदस्थ किया जाता है।

2. उपरोक्तानुसार श्री मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय शुक्ला, भा.व.से. (1987), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, केवल सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्रमांक/13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	सोनपुरी प.ह.नं. 16	0.334	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	सोनपुरी देउरगांव मोहतरा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्रमांक/14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	बरगांव प.ह.नं. 19	0.477	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	सोनपुरी देउरगांव मोहतरा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्रमांक/15/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	देऊरगांव प.ह.नं. 19	0.152	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	सोनपुरी देऊरगांव मोहतरा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प.ह.नं. 20	4.993	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत शंकरपाली माईनर 1 एवं 2 के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	धनगांव प.ह.नं. 17	1.164	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माईनर 1 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	जशपुर प.ह.नं. 06	118.021	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 01, खरसिया, जिला-रायगढ़.	साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	(1)	(2)
	198/2	0.032
	159/5	0.012
	242	0.089
रायगढ़, दिनांक 1 सितम्बर 2018	91/1	0.065
	150/2	0.049
	164/3	0.073
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य	136/10	0.024
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	175/1	0.085
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	148/1	0.089
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन,	171/10	0.053
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	141	0.045
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013	173/1	0.125
कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया	157/1	0.121
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	171/20	0.013
	140/1	0.030
अनुसूची	182/11	0.024
(1) भूमि का वर्णन—	175/4	0.057
(क) जिला-रायगढ़	181/4	0.049
(ख) तहसील-सारंगढ़	138/2	0.004
(ग) नगर/ग्राम-धूता	198/1	0.057
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.295 हेक्टेयर	161/1	0.036
	61/2	0.073
	159/6	0.012
खसरा नम्बर	155/6	0.020
रकबा	205/2	0.040
(हेक्टेयर में)	201/2	0.008
(1)	201/1	0.060
	166/3	0.170
56/1	66	0.154
161/3	235/1	0.105
138/3	68/2	0.091
61/1	72/1ख	0.011
65/3	199/4	0.032
199/2	156/1/ख	0.036
162/2	73/4	0.022
166/2	195/1	0.050
166/1	70/3	0.027
64/2	75/2	0.052
65/2	79/2	0.063
202	80/2	0.025
181/11	159/7	0.012
68/1	81/1	0.061
196/4	137/3	0.028
69/1/ख	171/9	0.101
70/1	241/2	0.064
176/2	181/6	0.044
180/1	181/10	0.053
167		
163/3		

(1)	(2)	(1)	(2)
95/2	0.009	136/3	0.012
171/19	0.014	134/24 ग	0.108
142/6	0.121	212/1	0.032
174	0.210	138/1	0.012
96/2	0.028	56/2	0.036
192/10	0.044	206/1	0.081
151/3	0.012	61/4	0.016
134/24 ख	0.108	241/1	0.065
181/9	0.036	97/2	0.009
211/1	0.013	62/2	0.036
161/2	0.036	64/1	0.089
213/3	0.168	62/3	0.146
200/2	0.016	62/4	0.089
61/3	0.170	159/1	0.077
197/1	0.057	148/3	0.089
199/5	0.033	196/3	0.057
244/2	0.010	164/5	0.098
62/1	0.093	236/1 ख	0.015
207/1	0.008	195/2	0.032
207/2	0.008	156/1/क	0.101
80/1	0.045	154/2	0.016
247/1 क	0.081	98	0.162
164/4	0.098	75/1	0.071
153/2	0.040	161/4	0.073
206/2 ख	0.013	159/4	0.011
194/2	0.021	81/2	0.061
154/5	0.025	83/1	0.038
70/2	0.028	143/1	0.040
154/3	0.016	92/1	0.074
78/1	0.041	93/2	0.044
164/2	0.073	145/1	0.085
154/4	0.012	212/6	0.102
247/2	0.081	96/1	0.027
243	0.247	135	0.454
142/4 क	0.024	165/1	0.157
213/1	0.167	185/1	0.251
92/2	0.050	171/18	0.053
93/12	0.041	136/1	0.012
136/5	0.065	181/8	0.036
137/1	0.044	151/9	0.032
95/1	0.048	151/8	0.045
144	0.121	149/2	0.033
184	0.113	171/14	0.061
137/7	0.045	210/3	0.081
134/24 क	0.108	142/2क	0.043
175/3	0.056	180/3	0.113
		181/2	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
136/6	0.016	171/1	0.065
182/6	0.016	152/1ख	0.038
182/4	0.016	146	0.299
211/4	0.006	158/4	0.047
211/3	0.006	204/1	0.069
152/1ग	0.062	142/7	0.182
137/5ख	0.024	210/1	0.044
139/1	0.040	171/22	0.051
235/2	0.053	151/5	0.044
171/11	0.164	211/2	0.024
142/3ख	0.178	181/12	0.041
152/2	0.146	236/1क	0.028
143/3	0.020	155/1	0.020
151/1	0.020	155/5	0.032
151/2	0.093	158/2	0.032
93/5	0.004	162/3	0.089
153/1	0.147	244/1	0.022
154/1	0.081	205/3	0.040
155/3	0.040	163/1	0.061
157/2	0.020	173/2	0.085
181/3 क	0.033	171/17	0.127
205/5	0.012	181/7	0.044
183/3	0.035	212/5	0.045
244/3	0.006	199/1	0.016
165/2	0.081	93/4	0.004
171/15	0.065	171/23	0.061
182/8	0.032	171/8	0.040
182/1	0.053	193/2	0.053
197/2	0.073	65/1	0.020
234	0.085	150/1	0.048
142/2ग	0.042	134/2	0.291
204/2	0.052	172/10	0.038
182/3	0.046	137/2	0.089
138/4	0.012	170/4	0.097
142/8	0.174	171/5	0.057
170/3	0.024	145/2	0.032
254/2	0.059	171/6	0.070
172/9	0.008	148/2	0.089
149/5	0.020	151/7	0.061
149/3	0.033	151/6	0.046
136/2	0.069	136/9	0.016
136/4	0.029	137/4	0.024
140/2	0.031	171/4क	0.017
136/7	0.016	137/8	0.053
136/8	0.016	210/2	0.049
212/4	0.020	142/2ख	0.093
212/3	0.020	142/3क	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
142/4ख	0.028	149/1	0.029
213/2	0.167	157/3	0.012
147	0.085	143/2	0.036
151/10	0.032	142/4ग	0.029
212/2	0.141	209	0.181
152/1क	0.038	181/5	0.049
200/3	0.036	151/4	0.053
155/2	0.020	171/2	0.116
156/2	0.130	254/1	0.036
158/3	0.033	171/7	0.081
97/1	0.009	176/1	0.129
162/4	0.085	160	0.126
205/4	0.016	205/1	0.040
164/1	0.103	97/3	0.009
171/3	0.116	241/3	0.251
180/2	0.073	196/1	0.014
182/9	0.040	171/12	0.081
193/1	0.064	181/1	0.049
196/2	0.028	93/3	0.073
212/7	0.073	194/1	0.062
171/24	0.057	198/3	0.032
175/2	0.073	149/6	0.018
235/3	0.052	171/25	0.027
139/3	0.020	181/3ख	0.032
170/1	0.190	169	0.072
192/5	0.070	142/5	0.174
171/16	0.127	170/2	0.236
149/4	0.014	163/2	0.120
171/13	0.046	171/21	0.050
150/3	0.113		
182/2	0.027	योग	324 20.295
182/10	0.024		
181/13	0.040	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज	
181/14	0.040	निर्माण हेतु.	
182/5	0.016		
182/7	0.016	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़	
137/6	0.025	के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
210/4	0.089		
143/4	0.021	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
159/3	0.012	शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	